

एक प्रदेश, एक संपत्तिकर निर्धारण प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय के अपर निदेशक अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि पूरे राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स की एक समान कर निर्धारण प्रणाली लागू करने के लिये शहरों की जीआईएस (GIS) मैपिंग की जा रही है।

प्रमुख बंदी

- पहले चरण में उत्तराखंड के 14 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से 4 शहरों- देहरादून, हरद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर की जीआईएस मैपिंग अंतिम चरण में है।
- दूसरे चरण में सभी नगर पंचायतों में हाउस टैक्स के लिये सर्वे किया जाएगा।
- इस योजना के तहत नगर निकाय क्षेत्र का जीआईएस मैपिंग कर सभी आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों की जियो रैकिंग की जाएगी तथा सभी भवनों को एक यूनिक आईडी नंबर युक्त स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा।
- इस आईडी में भवन की फोटो, आकार, कवर एरिया, मकान मालिक का नाम, मकान का नंबर सहित सभी विवरण दर्ज होंगे।